तीन नए कानूनों से देश में 2029 तक सुनिश्चित होगा समयबद्ध न्याय

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 - अंक : 10 - जनवरी 2026

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में

भारतीय सहकारिता का बढ़ा वैश्विक वर्चस्व

स्वरोजगार से होगा आत्मनिर्भर व समृद्ध भारत का निर्माण 26

गर्व, एकता और आत्मविश्वास का साल रहा 2025 27

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
जनवरी 2026, अंक 10, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
राजीव शर्मा
समूह संपादक
वेद प्रकाश सेतिया

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:
MINISTRY OF COOPERATION
NCUI हाट
CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकता है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़े प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

आवरण कथा

06

भारतीय सहकारिता का बढ़ा वैश्विक वर्चस्व

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन के साथ ही वैश्विक सहकारिता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। यह भारत के लिए गतिशील प्रगति, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया दौर साबित हुआ है।

12

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन सुलभ और मजबूत बनाया : श्री अमित शाह

स्वास्थ्य का क्षेत्र मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एक स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

सुधार की गति बनाए रखने और परिणाम के लिए प्रगति जरूरीः प्रधानमंत्री श्री मोदी — 14

बच्चों, युवाओं और सामाजिक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा दे रहा 'नमोत्सव' — 16

विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करेगी हमारी युवा शक्तिः प्रधानमंत्री श्री मोदी — 18

व्यापार, पर्यटन व रणनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन रहा अंडमान और निकोबार — 20

तीन नए कानूनों से देश में सुनिश्चित होगा समयबद्ध न्याय — 24

स्वरोजगार से होगा आत्मनिर्भर व समृद्ध भारत का निर्माण — 26

29

लाठीकाटा समिति ने जन औषधि केंद्र खोलकर आदर्श स्थापित किया

समावेशी विकास और समृद्धि की मुहिम

भारत में सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न बहुआयामी पहलों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थानों तक सहकारी नेटवर्क सुदृढ़ हो रहा है। भारत सरकार के समन्वय से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में देश में सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं डिजिटलीकरण, महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की मजबूत नींव रखी गई है। सहकारी समितियों में पारदर्शी शासन और नवाचार के माध्यम से समावेशी एवं सतत सहकारी भविष्य की सुदृढ़ बुनियाद स्थापित गई है। इस दौरान सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें 30,000 से अधिक नए पैक्स, डेयरी एवं मत्स्यिकी समितियों का गठन, सहकारी बैंकों में सुधार करते हुए उन्हें रिजर्व बैंक के दायरे में लाना और पांच लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करना, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं स्थापित करना और ग्रामीण विकास के लिए सहकारिता को प्रमुख माध्यम बनाना शामिल हैं। इसी दौरान देश की सबसे बड़ी सहकारी टैक्सी सेवा समिति बनाने के लक्ष्य के साथ 'भारत टैक्सी' की अनूठी पहल की गई है।

इन विविध पहलों के जरिए 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी क्षेत्र के कार्य-व्यवसाय का विस्तार किया गया है और सहकारी समितियों को करीब 30 क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। समितियों का विस्तार और सशक्तीकरण कर उनसे ग्रामीण स्तर पर किसानों को जोड़ा जा रहा है और 15,793 डेयरी और मत्स्यिकी समितियों को मजबूत किया गया है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा और शहरी सहकारी बैंकों के विस्तार से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हो रही है।

नई पहलों के तौर पर स्वास्थ्य, जीवन, कृषि और दुर्घटना बीमा को सहकारी मॉडल पर लाने की योजना है। ऑर्गेनिक क्षेत्र में भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल ऑर्गेनिक्स जैसी राष्ट्रीय लैब चेन स्थापित की जा रही हैं, ताकि किसानों को वैश्विक बाजार मिल सके।

ग्रामीण और कृषि सशक्तीकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है और इथेनॉल उत्पादन में मक्के के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और ग्रामीण आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय के तहत नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लाई गई, जिसमें युवाओं, महिलाओं, और कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर है। पैक्स के कंप्युटरीकरण सहित कई गतिविधियों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये सभी कदम भारत को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।■

जय सहकार

अब भारत ने तय किया है कि आने वाले 10 वर्षों में देश को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करना है। 140 करोड़ देशवासियों का यही संकल्प होना चाहिए। आज की पीढ़ी ही देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे उनकी योग्यता और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। इसलिए उन्हें ही राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखकर हम नई पॉलिसी बनाने में जुटे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

किसान किसी भी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता व सतत समृद्धि के आधार होते हैं। किसान सम्मान निधि हो, एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हो या कृषि उत्पादों को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़कर किसानों की समृद्धि के अभिनव प्रयास हों, मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसानी निरंतर आधुनिक व स्वावलंबी हुई है।

शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सहकारी संस्थाएं केवल आर्थिक इकाइयां नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सशक्त वाहक हैं। गिफ्ट मिल्क एवं शिशु संजीवनी जैसे कार्यक्रमों का विशेष फोकस आकांक्षी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी विद्यालयों पर है। यह समावेशी विकास राष्ट्र की प्रगति को मजबूती प्रदान करता है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

देश के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने विभिन्न नए मॉडल बायलॉज को अपनाते हुए क्रेडिट, बैंकिंग, डेयरी, मत्स्य पालन सहित अनेक क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनके माध्यम से सहकारिता क्षेत्र के विकास एवं विस्तार को नई गति मिली है।

श्री मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारिता की ताकत अब स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सशक्त बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पैक्स, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पैक्स की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि 'सहकारिता से समृद्धि' का मंत्र जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से साकार हो रहा है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

सहकारिता की मिसाल: भारत टैक्सी ने दिखाई समृद्धि व सेवा की नई राह

सहकार जागरण टीम

भारत में सहकारिता की मुहिम का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। नए साल की शुरुआत में लॉन्च की गई भारत टैक्सी ने इस मुहिम में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया है।

राइड हेलिंग सेवा के क्षेत्र में एक नए मॉडल के साथ बाजार में उतरी भारत टैक्सी ड्राइवरों व यात्रियों दोनों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे ड्राइवरों को कैब एप्लीकेशंस पर ज्यादा कमीशन, पॉलिसी में अचानक बदलाव और इनकम की अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा। ड्राइवरों को इस सेवा से जुड़ने के लिए एक छोटा सा सेवा शुल्क अदा करना होगा। यात्रियों द्वारा भुगतान किया गया पूरा किराया ड्राइवरों को मिलेगा। निजी कैब सेवाओं की तरह उसे किसी कंपनी को न तो कमीशन देना होगा, न ही सरचार्ज।

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां न कमीशन की लूट है, न मौसम और पीक ऑवर का बहाना। यहां किराया हमेशा पारदर्शी, स्थिर और लोगों के हित में रहता है। बारिश हो, ट्रैफिक पीक टाइम हो या बैटरी कम हो जाए, किराए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। चौबीसों घंटे उपलब्ध यह सेवा हर समय यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए तत्पर है। आसान व सुगम यात्रा के लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग और हर राइड में भरोसे का आश्वासन देती है। सस्ती, सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद टैक्सी सेवा जनता के हित में जनता के लिए है। यह सेवा रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है। यह युवाओं के लिए अपनी क्षमता और संभावनाओं को साकार करने का सुअवसर है। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सदस्य उसके मालिक भी हैं और लाभार्थी भी। यह स्थाई आजीविका, वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रदान करता है।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के जरिए संचालित इस प्लेटफार्म पर लाखों यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं और रोजाना 40 से 45 हजार नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइवर-फर्स्ट नजरिया है। यात्रियों द्वारा भुगतान किया गया पूरा किराया ड्राइवर की जेब में जाएगा। इसके अलावा यह प्लेटफार्म ड्राइवरों को अन्य कई तरीकों से भी मदद पहुंचाता है। दुर्घटनाओं या आपात स्थितियों के दौरान सहायता और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी प्रदान करता है। ये प्रावधान न केवल ड्राइवर की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि कोऑपरेटिव ढांचे में विश्वास को भी मजबूत करते हैं। इस पहल का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को कोऑपरेटिव सिद्धांतों के साथ मिलाकर परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन को मजबूत करना है। साथ ही नागरिकों को किफायती, सुरक्षित और सुलभ मोबिलिटी प्रदान करना है। यह कैब ड्राइवरों को ज्यादा इनकम, निजी कैब कंपनियों पर कम निर्भरता और ज्यादा बराबरी वाले मोबिलिटी इकोसिस्टम का वादा करती है। सह सेवा शहरी अर्थव्यवस्था में सहकारी आंदोलन को नई गति दे सकती है।

इस सेवा के संबंध में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है कि देश में कई कंपनियां टैक्सी परिचालन का काम करती हैं। लेकिन उनमें मुनाफा ड्राइवर के पास नहीं, बल्कि मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय की पहल के तहत शुरू की गई इस सेवा का एक-एक पैसा ड्राइवर भाइयों के पास जा रहा है। रोजगार की नई संभावना खुली है। ड्राइवरों के लिए बीमा की व्यवस्था की गई है। टैक्सी पर एडवरटाइजमेंट की व्यवस्था होगी और पूरा मुनाफा ड्राइवर के पास ही जा रहा है। इससे यात्रियों को सहूलियत भी हो रही है और टैक्सी ड्राइवर का मुनाफा भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह भारत की सबसे अग्रणी टैक्सी परिचालन कंपनी बन जाएगी। इससे सहकारिता आंदोलन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और लोगों की समृद्धि का कारण बनेगा। ■

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में

भारतीय सहकारिता का बढ़ा वैश्विक वर्चस्व

सहकार जागरण टीम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन के साथ ही वैश्विक सहकारिता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। यह भारत के लिए गतिशील प्रगति, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक नया दौर साबित हुआ है। सामाजिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की सशक्त भूमिका को मान्यता देने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 'सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है' विषय के तहत मनाए गए इस वर्ष ने गरीबी से लड़ने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए समुदाय संचालित व्यावसायिक मॉडलों की पूरी क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर जो कदम उठाए गए और राज्यों के स्तर पर जिन कार्यक्रमों, अभियानों और पहल का आयोजन किया गया उससे न सिर्फ सहकारिता को लेकर जागरूकता बढ़ी, बल्कि भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई अंतरराष्ट्रीय पहचान और दिशा मिली है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता का दबदबा बढ़ा है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मनाने की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलांयस के सम्मेलन में किया गया था। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की आवाज बुलंद हुई। दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी संस्थाओं वाली भारतीय सहकारिता की आवाज को अब गंभीरता से लिया जाने लगा है। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का औपचारिक उद्घाटन और सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महासभा की

संयुक्त राष्ट्र के पहल से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मिली नई अंतरराष्ट्रीय पहचान और भविष्य की दिशा

वैश्विक स्तर पर बुलंद हुई भारतीय सहकारिता, घरेलू स्तर पर लोगों में बढ़ी जागरूकता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका हुई मजबूत

देश में पहली बार बनी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एवं नमक कोऑपरेटिव, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी हुई लागू

बैठक में दिल्ली में की गई। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की धाक जमाने में सफलता मिली। आईसीए विश्व भर में सहकारी समितियों की आवाज के रूप में कार्य करता है। यह संवाद, क्षमता निर्माण और वकालत के लिए सहकारी समितियों को वैश्विक मंच प्रदान करता है और एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहकारी समितियों के महत्व का समर्थन करता है। इसका मिशन सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और सतत सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के स्थायी सिद्धांतों पर आधारित है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के कोने-कोने में आयोजित सहकारिता सम्मेलनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान सहकारिता की अलख जगाने वालों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और सहकारिता के मंत्र की महिमा के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी, कुपोषण और बेघर लोगों के हितों का ध्यान सहकारिता के माध्यम से रखा जा सकता है। किसानों को उनकी खेती की जरूरत के सभी इनपुट और उपज की खरीद में सहकारिता की भूमिका का महत्व भी उन्होंने समझाया।

भारत में सहकारिता प्राचीन समय से ही जन-जीवन का आधार रहा है। हमारे कृषि प्रधान समाज में तो यह रोजमर्रा के कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा है। 121 वर्ष पहले 1904 में संगठित रूप से सहकारिता की

शुरुआत के बाद इसे आधुनिक और प्रभावी दिशा वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मिली। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से सहकारी मूल्य श्रृंखला की हर कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से 100 से अधिक परिवर्तनकारी पहल शुरू की हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रालय सहकारी .समितियों को गतिशील, जन-केंद्रित उद्यमों में विकसित होने में सक्षम बना रहा है जो सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों, अभियानों एवं पहलों पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की वार्षिक रिपोर्ट भारत के सहकारी संस्थानों की सामूहिक उपलब्धियों को दर्शाती है। इसमें उन अभियानों, नवाचारों और ज्ञान साझाकरण प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है जो मिलकर एक सहकारी, टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया को आकार देने में भारत के नेतृत्व को उजागर करते हैं।

भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण: प्रधानमंत्री

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, 'सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 भारत और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जिसने यह दिखाया है कि सहकार कैसे समावेशी और टिकाऊ विकास को गति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने वैश्विक सहकारी दृष्टिकोण को आकार देने

> अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भारत और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े सहकारी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है जिसने यह दिखाया है कि सहकार कैसे समावेशी और टिकाऊ विकास को गति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष ने वैश्विक सहकारी दृष्टिकोण को आकार देने में भारत के नेतृत्व को पुनः स्थापित किया।
>
> -श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

में भारत के नेतृत्व को पुनः स्थापित किया। इस वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों ने सहकारी समितियों के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रचार गतिविधियां, क्षमता निर्माण प्रयास और सामुदायिक पहल की हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन न केवल भारत की समृद्ध सहकारी विरासत का उत्सव है, बल्कि सहकारिता के माध्यम से वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान भी है। 'सहकार से समृद्धि' के शाश्वत मूल्यों से प्रेरित होकर भारत का सहकारी आंदोलन 2047 तक विकसित भारत और विश्वास, सहयोग और साझा समृद्धि पर आधारित विश्व की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहा है।'

जागरूकता को बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का मुख्य लक्ष्य सतत विकास और गरीबी उन्मूलन पर सहकारी समितियों के स्थायी प्रभाव के बारे में विश्वव्यापी जन जागरूकता बढ़ाना था। इसमें उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर सहकारी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, वैश्विक स्तर पर सहायक कानूनी और नीतिगत ढांचों की वकालत करना और युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए सार्थक नेतृत्व को प्रेरित करना शामिल था। पूरे वर्ष के दौरान

आईवाईसी 2025 की प्रमुख गतिविधियां

- जागरूकता अभियान और आउटरीच गतिविधियां में वृद्धि
- कार्यशालाएं, सेमिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम को गति
- पैदल मार्च, रैलियां और अन्य जन भागीदारी अभियान चलाए
- नई पहलों और कार्यक्रमों के शुभारंभ हुए
- प्रदर्शनियां, मेले और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां में बढ़ावा
- कौशल विकास, रोजगार और किसान केंद्रित गतिविधियां जगह-जगह आयोजित
- महिला सशक्तीकरण और युवा कल्याण पहलों को नई ऊर्जा
- सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी
- सहकारी समितियों में नई आईटी तकनीक का उपयोग
- स्वच्छता में सहकार पहल

सहकारी समितियों और सहायक संस्थानों ने शिक्षा, जनसंपर्क, सहयोगात्मक साझेदारी और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत गतिविधियों का दायरा व्यापक और बहुआयामी था, जिसमें जागरूकता अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और नीतिगत संवाद शामिल रहे। इन सामूहिक प्रयासों से सरकारी संस्थानों, सहकारी संघों, विकास एजेंसियों और आम जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने

में मदद मिली जिससे सहकारी क्षेत्र की परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में क्षमता को बल मिला। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, नोडल विभागों और सहकारी संस्थानों के सक्रिय सहयोग ने इस राष्ट्रव्यापी उत्सव को सुगम बनाया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और सहकारी संगठनों द्वारा लोगो और डाक टिकट का उपयोग किया। इसमें राज्यों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। देश में पहली बार त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का गठन हो, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन हो, देश में पहली बार नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत हो, दुग्ध क्रांति 2.0 की शुरुआत हो, डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई कोऑपरेटिव बनाने और सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा सहित अन्य दर्जनों पहल से भारतीय सहकारिता ने नई उड़ान भरी है। इनसे सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल बनाने में भी मदद मिलेगी।

सहकारिता क्षेत्र में परिवर्तन का नया युगः अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट में दिए अपने संदेश में कहा, 'भारत में सहकारिता आंदोलन परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा युग जो नवाचार, समावेशिता और राष्ट्र की समृद्धि को गति देने के सामूहिक संकल्प द्वारा परिभाषित है। भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इसे नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन और महासभा में आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई अग्रणी पहलों जैसे कि एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल ने भारत के सहकारी क्षेत्र को विस्तार दिया है। ये संगठन भारतीय किसानों को वैश्विक बाजारों से जुड़ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बना रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को भी वैश्विक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करके यह पहलें इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि सहकारी शक्ति किस प्रकार स्थानीय क्षमता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सफलता में बदल सकती है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो कुशल और भविष्य के लिए तैयार सहकारी कार्यबल के पोषण हेतु नेतृत्व विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती है।'

इन प्रयासों से तय होगा सहकारिता का भविष्य

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहकारिता के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विकास को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पर सहायक कानूनी और नीतिगत ढांचों की वकालत करना और युवाओं को सहकारी आंदोलन को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए प्रेरित करने वाले नेतृत्व को प्रोत्साहित करना था। सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। इसमें शासन, पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। सहकारी समितियों के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं और नवाचार के लिए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन प्रयासों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिक्षा और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा ताकि समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम लचीले सहकारी उद्यम तैयार किए जा सकें।

सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन के लिए नीतिगत और कानूनी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे जो सहकारी समितियों को समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रेरक के रूप में मान्यता दें। साथ ही फाइनेंस, मार्केट और टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच को सुगम बनाएं। ऐसे सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी

समितियां सहयोगी माहौल में काम करें जो विकास, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ावा दे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिक टेक्नोलॉजी का एकीकरण सहकारी समितियों की परिचालन क्षमता, पहुंच और सेवा वितरण को बढ़ाएगा। डिजिटल टूल्स सहकारी समितियों को प्रासंगिक बने रहने, सदस्यों की सहभागिता बढ़ाने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाएंगे।

सतत और समावेशी विकास

सहकारिता क्षेत्र का विस्तार होने से सहकारी समितियां सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी प्रथाओं को अपनाएंगी, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, पारिस्थितिक स्थिरता और सामाजिक समानता शामिल हैं। समावेशी मॉडल व्यापक आर्थिक भागीदारी को सुगम बनाएंगे, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों तक लाभ पहुंचेगा और सामाजिक न्याय एवं सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सहकारी समितियों के बीच साझेदारियां सहकारी आंदोलन के प्रभाव को मजबूत करेंगी। यह गठबंधन सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक जीवंत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करेंगे।

यह प्राथमिकताएं सहकारिता मंत्रालय के उस एजेंडे के अनुरूप हैं जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को समावेशी और सतत विकास की आधारशिला बनाना है। यह प्रतिबद्धता 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसमें सहकारी समितियों को ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं, साझा समृद्धि और सतत राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाना तय किया गया है।

महिला एवं युवा सशक्तीकरण पर फोकस

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान महिलाओं और युवाओं को सहकारिता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सहकारिता के सिद्धांतों और इतिहास के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं और पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारिता की समझ को बढ़ाना और युवाओं को सहकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों, संगठन और फेडरेशन के अलावा राज्य स्तरीय सहकारी संघों ने भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर विकसित भारत में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से युवाओं और महिलाओं

की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। समर्थ युवा, समर्थ सहकार की भावना से प्रेरित देशभर में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सहकारी उद्यमिता, स्वरोजगार, डेयरी, ऋण समितियों और स्टार्टअप में आर्थिक विकास जैसे विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से सामूहिक उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रख कर आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, सहकारी साक्षरता शिविर और सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका फोकस युवा और महिला सहकारी सदस्यों के बीच नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर था। यही नहीं, कई राज्यों में नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जिसका उद्देश्य युवा और महिला नेताओं की अगली पीढ़ी को पोषित करना था, उन्हें सहकारी शासन को मजबूत करने और इस क्षेत्र में समावेशी, सतत विकास को गति देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दूरदृष्टि प्रदान करना था। राज्य स्तरीय युवा सहकार संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसके माध्यम से विकास में सहकारिता की भूमिका पर छात्रों और युवाओं से बातचीत की गई और उनमें सहकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की गई।

सहकारी निर्णय लेने में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र में नई ऊर्जा, नवाचार और स्थिरता लाने पर भी इस वर्ष के दौरान ध्यान केंद्रित किया गया। इससे कौशल आधारित रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला। युवाओं पर केंद्रित मैराथन और सेमिनारों में भी छात्रों और युवा सहकारी सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन गतिविधियों ने सहकारी आंदोलन में युवाओं की सहभागिता, जागरूकता और नेतृत्व को प्रोत्साहित करके अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सूत्र वाक्य 'सहकार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना' को मजबूत किया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 ने देश में न सिर्फ सामाजिक समानता को मजबूत किया और भागीदारी को व्यापक बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सहकारी समितियां समावेशी और भविष्योन्मुखी बनी रहें, बल्कि जीडीपी में सहकारिता का योगदान बढ़ाने के प्रयासों को नई राह दिखाई है। सहकारिता बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं, इस थीम को इस वर्ष ने पूरी तरह से सफल बनाया।■

अहमदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन सुलभ और मजबूत बनाया : श्री अमित शाह

सहकार जागरण टीम

- सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आयुष्मान भारत व मिशन इंद्रधनुष जैसी पहलों ने देश का स्वास्थ्य परिदृश्य बदला
- पांच लाख तक मुफ्त इलाज सुविधा, सीएचसी व पीएचसी का व्यापक नेटवर्क और देशभर में जनऔषधि केंद्र खुले

स्वास्थ्य का क्षेत्र मूल रूप से सेवा का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एक स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सेवा और मेडिकल शिक्षा के जरिए स्वस्थ भारत के निर्माण में इसने एक सुनहरा अध्याय जोड़ा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गुजरात के अहमदाबाद में आईएमए के 100वें राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के सामने विकसित भारत के निर्माण का यह संकल्प रखा है कि आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तब भारत पूरे विश्व में सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने इसके लिए मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा एवं उत्साह आदि सभी प्रकार से 'हेल्थ डेमोग्राफी' के सृजन की पहल की। श्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार विकसित भारत में एक मजबूत हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए कटिबद्ध है। श्री मोदी के नेतृत्व में देश में 2014 से 2025 के दौरान समग्र दृष्टिकोण के साथ एक हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है।

आईएमए के पांच हजार से अधिक प्रतिनिधियों के बीच 'स्वस्थ जीवन के लिए 100 कदम' नामक पुस्तक का विमोचन कर

स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में व्यापक बदलाव

पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सीटों को 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार कर दिया है, जिससे हर साल इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) का निरंतर विस्तार हो रहा है और जल्द ही एम्स से पीएचसी-सीएचसी तक टेलीमेडिसिन और वीडियोग्राफी के जरिए कंसल्टेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। श्री शाह ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में 102 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। जहां वर्ष 2013-14 में भारत का स्वास्थ्य बजट सिर्फ 37 हजार करोड़ रुपए था, वह आज एक लाख 28 हजार करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि एक लाख 81 हजार आयुष मंदिर को ताकत देना, इस देश के गरीब और गांव के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, कालाजार में 90 प्रतिशत से ज्यादा सुधार, डेंगू से मृत्यु दर का घट कर एक प्रतिशत होना, मातृ मृत्यु दर का 25 प्रतिशत कम होना, संस्थागत प्रसव का 20 प्रतिशत बढ़ना और शिशु मृत्यु दर आधी होना इसलिए संभव हुआ, क्योंकि हमारी योजनाएं सिर्फ घोषित नहीं, बल्कि लागू हुई हैं। मलेरिया के मामलों में 97 प्रतिशत की कमी यह बताती है कि भारत जल्द मलेरिया मुक्त होने वाला है।

श्री शाह ने कहा कि आईएमए के माध्यम से पिछले 100 वर्षों में डॉक्टरों ने बीमारों की सेवा और आयु बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में ले जाने में आईएमए अपनी भूमिका तय करे। आईएमए का रोल देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत व अभेद्य बनाने का होना चाहिए और इसके लिए अपने योगदान के विभिन्न आयामों पर फिर से विचार करें कि देश को आगे कैसे ले जाएं? श्री शाह ने कहा कि आईएमए को देश की आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ना है और इसके लिए हमें बीमारी (इलनेस) की बजाय स्वास्थ्य (वेलनेस) को मुख्य अवधारणा बनाना होगा। दवा के साथ-साथ अच्छी जीवनशैली के लिए सलाह और मार्गदर्शन देने पर जोर देते हुए उन्होंने आयुष्मान भारत व जेनेरिक दवाओं को महत्वपूर्ण कहा। देश में आजादी के पूर्व से अब तक सभी डॉक्टरों ने गरीब मरीजों की जो सेवा की है, उसका वह हृदय से सम्मान करते हैं।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन

श्री शाह ने कहा कि इसके लिए सरकार ने सबसे पहले हर घर में शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। इस अभियान का स्वास्थ्य से गहरा जुड़ाव है, क्योंकि शहर, गांव और कस्बे स्वच्छ हो जाने से बहुत सारी बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। इसके बाद सरकार ने 'फिट इंडिया मूवमेंट' और 'खेलो इंडिया' की शुरुआत की एवं योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जिससे योग को जीवन का हिस्सा बनाने वालों की संख्या में 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़े 'आयुष्मान भारत मिशन' को लागू किया गया है, जिसके तहत पूरे भारत में गरीबों को पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। राज्यों की योजनाओं को जोड़ लें तो देश के 70 प्रतिशत हिस्से में 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ़्त हो रहा है। 'आयुष्मान भारत मिशन' ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि आभा और मिशन इंद्रधनुष ने बच्चे के जन्म से ही उसके स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव रखी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट बढ़ाया है। सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में सस्ती जेनेरिक दवाओं की बड़ी शृंखला शुरू की और इंश्योरेंस से जीएसटी हटाकर उसे सस्ता किया है। चिकित्सा के नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत करते हुए श्री शाह ने कहा कि मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने मात्र से कोई सफल डॉक्टर नहीं बन सकता, बल्कि इस क्षेत्र में नैतिकता के सभी आयामों को भी मेडिकल शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए और यह जिम्मेदारी आईएमए की है। इसने जन्मपूर्व लिंग निर्धारण की समस्या को काफी हद तक कम भी किया है। श्री शाह ने आईएमए के त्याग, सेवा और निरंतर योगदान की सराहना करते हुए इस क्षेत्र के एथिक्स को फिर से परिभाषित करने और उसे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के मुताबिक बनाने के लिए एक टीम के गठन का आह्वान किया।

इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ नागरिकों का स्वास्थ्य सुधार

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार ही नहीं हो रहा है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य में अभूतपूर्व बदलाव लाने का काम भी हो रहा है। उन्होंने देश के चिकित्सकों को प्रेरित करते हुए कहा, 'आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं, उसे इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन योजनाओं के साथ और आपके प्रयासों के साथ पूरी तरह संरेखित करना होगा। तभी असली और बड़े परिणाम सामने आएंगे।' उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है, तो उसे उपचार करने वाले डॉक्टर में ही ईश्वर नजर आता है।

कोरोना संकट के समय देश में कई महत्वपूर्ण कार्यों और टीकाकरण में आईएमए के सहयोग को याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि उस दौरान 2500 से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित हुए और हेल्पलाइन पर 20 लाख से अधिक कॉल प्राप्त कर लोगों की मदद की गई। संकट के दौर में डॉक्टरों ने बहुत सराहनीय काम किया और अपनी सेहत की चिंता किए बगैर कर्तव्य पालन करते हुए लोगों की सेवा की। ■

प्रगति की 50वीं बैठक का आयोजन

सुधार की गति बनाए रखने और परिणाम के लिए प्रगति जरूरी: प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

- प्रगति के नेतृत्व वाले इकोसिस्टम ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की गति को किया और तेज
- राष्ट्रीय हित में पूरी हुईं सभी परियोजनाएं
- विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में प्रगति निभा रहा एक उत्प्रेरक की भूमिका

वर्ष 2014 से सरकार ने कार्य-पूर्णता और जवाबदेही को संस्थागत बनाने के लिए काम किया है। एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई है जिसमें काम को लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाया जाता है और इसे समय और बजट के भीतर पूरा किया जाता है। पहले शुरू की गईं अधूरी परियोजनाएं या जिन्हें भुला दिया गया था, उन्हें राष्ट्रीय हित में पुनर्जीवित और पूरा किया गया है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान पांच राज्यों में फैली 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत की पांच आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कही।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों से अटकी इन परियोजनाओं को प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत लाने के बाद पूरा किया गया या निर्णायक रूप से खोला गया। इनमें असम में बोगीबील रेल-सड़क पुल शामिल है, जिसकी परिकल्पना पहली बार 1997 में की गई थी। जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बरामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू हुआ था। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परिकल्पना 1997 में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार को 2007 में मंजूरी दी गई और गदरवारा और लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना को क्रमशः 2008 और 2009 में स्वीकृत किया गया था। ये परिणाम लगातार उच्चस्तरीय निगरानी और अंतर-सरकारी समन्वय के प्रभाव को दर्शाते हैं।

प्रगति सहयोगी संघवाद का एक प्रभावी मॉडल

परियोजनाओं के केवल इरादे की कमी के कारण नहीं, बल्कि समन्वय की कमी और अलग-अलग काम करने पर आधारित कार्यप्रणाली के कारण असफल होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए प्रगति सभी हितधारकों को एक मंच पर लेकर आई। इससे साझा परिणाम हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि प्रगति सहयोगी संघवाद का एक प्रभावी मॉडल है। यहां केंद्र और राज्य एक

टीम के रूप में काम करते हैं और मंत्रालय और विभाग अलग-अलग काम करने के परे जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाने और और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निवेश करने का जिक्र करते हुए उन्होंने हर मंत्रालय और राज्य से योजना से लेकर क्रियान्वयन तक पूरे शृंखला को मजबूत करने तथा निविदा आमंत्रित करने से लेकर जमीन पर कार्यान्वयन तक देरी को कम करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अगले चरण के लिए अपनी अपेक्षाओं को साझा करते और सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के अपने विजन को बताते हुए कहा कि सरल बनाने के लिए सुधार करें, कार्य-पूर्णता के लिए काम करें, प्रभाव डालने के लिए परिवर्तन करें। उन्होंने कहा कि सुधार का मतलब प्रक्रियाओं से समाधान की ओर बढ़ना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता के लिए प्रणाली को अधिक मित्रवत बनाना होना चाहिए। काम करने का मतलब समय, लागत और गुणवत्ता पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परिणाम-संचालित शासन प्रगति के माध्यम से मजबूत हुआ है और अब इसे और आगे ले जाना चाहिए। परिवर्तन का माप इस बात से किया जाना चाहिए कि नागरिक समय पर सेवा अदायगी, तेज शिकायत निवारण और जीवन की बेहतर सुगमता के बारे में वास्तव में क्या महसूस करते हैं।

विकसित भारत @ 2047 को न केवल एक राष्ट्रीय संकल्प, बल्कि एक समयबद्ध लक्ष्य भी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रगति इसे हासिल करने के लिए एक ठोस उत्प्रेरक है। उन्होंने राज्यों को प्रोत्साहित किया कि वे मुख्य सचिव स्तर पर विशेष रूप से समाजिक क्षेत्र के लिए प्रगति जैसी व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान करें। प्रगति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए परियोजना जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति@50 केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है। भविष्य में प्रगति को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों के लिए तेजी से कार्यान्वयन, उच्च गुणवत्ता और मापने योग्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

बैठक के दौरान पीएम श्री योजना की समीक्षा करते समय प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम श्री योजना को समग्र और भविष्य के अनुकूल स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक बनाना चाहिए। इसका कार्यान्वयन अवसंरचना-केंद्रित नहीं, बल्कि परिणामोन्मुख होना चाहिए। पीएम श्री स्कूलों को राज्य सरकार के अन्य स्कूलों के लिए मानक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पीएम श्री स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे करने चाहिए। पिछले दशक में शासन की कार्य संस्कृति में आए बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब निर्णय समय पर लिए जाते हैं, समन्वय प्रभावी होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार के संचालन की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और इसका प्रभाव सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है।

> "प्रगति सेशन के दौरान, 40,000 करोड़ रुपए के अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया। इन कामों में सड़क, रेलवे, बिजली, पानी और कोयला जैसे सेक्टर शामिल हैं। पीएम श्री योजना से जुड़े पहलुओं का भी रिव्यू किया गया, जो हमारे देश में एक बेहतरीन शिक्षा सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हम पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। हम 'सरल बनाने के लिए सुधार, डिलीवर करने के लिए परफॉर्म, असर डालने के लिए ट्रांसफॉर्म' के विजन के साथ प्रगति इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह इकोसिस्टम विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने का एक शक्तिशाली जरिया है। प्रगति इकोसिस्टम की वजह से 377 अहम प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया गया। इन कामों से जुड़ी 94 प्रतिशत पेंडिंग समस्याओं को सुलझा लिया गया, जिससे देरी, लागत में बढ़ोतरी और कोऑर्डिनेशन में नाकामियों में कमी आई है। यह टीम वर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बाधाओं को तोड़ने का एक शानदार उदाहरण है।"
>
> -श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति के तहत 94 प्रतिशत मुद्दों का समाधान

अब तक प्रगति नेतृत्व वाले इकोसिस्टम द्वारा 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करने और बड़े पैमाने पर प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में योगदान का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि 2014 से प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इन परियोजनाओं के 3,162 पहचान किए गए मुद्दों में से 2,958 यानि लगभग 94 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। इससे देरी, लागत अधिकता और समन्वय विफलताओं में काफी कमी आई है। जैसे-जैसे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सुधार की रफ्तार बनाए रखने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रगति आवश्यक है।■

प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोले श्री अमित शाह

बच्चों, युवाओं और सामाजिक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा दे रहा 'नमोत्सव'

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जीवन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति संकल्पित, राष्ट्रसेवा को समर्पित व जनसेवा के लिए कटिबद्ध रहा है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी नीयत और निष्ठा से नेता बने हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गुजरात के अहमदाबाद में 'नमोत्सव' नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यक्त किया। बच्चों, युवाओं और सामाजिक लोगों के लिए नई प्रेरणा देने वाले इस महोत्सव में श्री शाह ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक से लेकर संगठन में विभिन्न दायित्वों, गुजरात के मुख्यमंत्री और अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी ने राष्ट्रसेवा के लिए त्याग, समर्पण व निरंतर श्रम के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण और उनका अनुसरण भी नीयत से किया है। वे एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नीयत, दृढ इच्छाशक्ति और लोगों का भला करने की इच्छा के आधार पर सर्वोच्च स्थान पर

- **श्री मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चिंताओं से मुक्त किया**
- **11 वर्षों में प्रधानमंत्री का 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का कल्याण यज्ञ उन्हें महान बनाता है**
- **जिस व्यक्ति के पास अपना एक कमरा भी नहीं है, उन्होंने चार करोड़ देशवासियों को दिया है घर**

पहुंचे हैं। एक विशिष्ट प्रकार का नेतृत्व, बचपन से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर देश में लाखों लोगों के जीवन में कार्यसंस्कृति का बीज बोने वाले नेता के रूप में उनका जीवन युवाओं के लिए एक आदर्श है।

देशवासियों में 2047 तक विकसित भारत का जगा विश्वास

श्री शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने जीवन के 75 साल पूर्ण किए, तब देश और दुनिया के कई लोगों ने सुझाव दिए कि इस अद्भुत व्यक्तित्व, जीवन और उनके जीवन की अद्भुत यात्रा को लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे देश और पूरी दुनिया में लोगों के जीवन की प्रेरणा बने प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीवन को नमोत्सव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस आयोजन में कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से श्री मोदी के जीवन, कर्तव्यों और उन सिद्धांतो को प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों के मन में 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का विश्वास जगाया है। श्री मोदी ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन नए मार्ग प्रशस्त करने, अपने प्रयासों को सफल बनाने के लिए अनेकानेक प्रयोग करने और देशभर में उस विचार के साथ सहमत लाखों लोगों की टीम बनाने में लगाया है। श्री शाह ने कहा कि यह यात्रा एक बेहद गरीब घर में अपना बचपन बिताने वाले एक सामान्य चाय वाले के परिवार के उस होनहार, जो सभी देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की उम्मीद का प्रतीक बन गया है, उसकी यात्रा की कहानी है। बेहद गरीबी से बाहर आए श्री मोदी को आज दुनिया के 29 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री और देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी को दुनिया भर से मिल रहा यह सम्मान और उनका व्यक्तित्व देशवासियों को बड़ी प्रेरणा प्रदान कर रहा है।

गरीबी में पले श्री मोदी ने करोड़ों गरीबों के कल्याण का मार्ग अपनाया

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी का जीवन भयानक गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कटुता की जगह अपने जीवन को गरीब कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ाया और करोड़ों गरीबों के कल्याण करने का संकल्प अपनाया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लेकर आए हैं। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने करोड़ों गरीबों को घर, पीने का शुद्ध पानी, शौचालय, बिजली, गैस सिलिंडर और प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज व बच्चों की पढाई की व्यवस्था प्रदान किया है। इसके साथ ही करोड़ों जरूरतमंद लोगों को पांच लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी सिर्फ 11 साल में ही देश के 60 करोड़ गरीबों को इन सभी चिंताओं से बाहर ले आए हैं। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के संकल्पों से देश के 27 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा को पार किया है। गरीब कल्याण का यह यज्ञ, एक गरीब घर में जन्मे श्री मोदी को महान बना रहा है।

सार्वजनिक जीवन में अहर्निश जनता की सेवा

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने अक्टूबर, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सार्वजनिक जीवन में उनके जीवन का जो चरण शुरू हुआ, वह आज देश में एक मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन श्री मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया कि अब तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सरपंच का चुनाव भी न जीता हो और सीधे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन गया हो। श्री शाह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी का कार्यकाल पूरे देश के सामने सुराज्य कैसे लाया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और आदर्श उदाहरण बन गया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पद्धति से बिजली की समस्या को जड़ से दूर करने के लिए ज्योतिग्राम योजना लागू की। इसके माध्यम से उन्होंने भारत में पहली बार गुजरात के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का कार्य किया।

श्री शाह ने कहा कि 24 वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी ने एक भी दिन न छुट्टी ली और न आराम किया, बल्कि अहर्निश जनता की सेवा के लिए मेहनत की है। उन्होंने कहा कि मां भारती को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने की इच्छा की पूर्ति के लिए यात्रा पर निकले श्री मोदी आज पूरे देश के किशोर, युवा और बच्चों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणास्रोत है। पूरी तरह पारदर्शी जीवन जीने वाले श्री मोदी के पास रहने के लिए अपना एक कमरा भी नहीं है, लेकिन उस महान व्यक्तित्व ने देश के चार करोड़ बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर प्रदान किया है।■

राजधानी दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन

विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करेगी हमारी युवा शक्ति: प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

युवा पीढ़ी जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा का प्रतिनिधित्व करती है। यही पीढ़ी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। वह उनकी क्षमता और आत्मविश्वास को देखते और समझते हैं, इसलिए उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा भी समझदारी से बोले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। महानता उम्र से नहीं बल्कि कर्मों और उपलब्धियों से परिभाषित होती है। युवा ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित करते हैं, और कई लोग इसे पहले ही साबित कर चुके हैं।

वर्तमान पीढ़ी को भाग्यशाली बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र उनकी प्रतिभा के साथ मजबूती से खड़ा है। आज देश प्रतिभा की खोज करता है, मंच प्रदान करता है और 140 करोड़ नागरिकों की शक्ति को उनकी आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। डिजिटल इंडिया की सफलता के साथ युवाओं के पास इंटरनेट की शक्ति और सीखने के संसाधन मौजूद हैं। इनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया और खेल में प्रगति करने वाले युवाओं के लिए खेलो इंडिया जैसी पहल शामिल हैं।

- **युवा ऐसे कार्य कर सकते हैं, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं, वे इसे साबित भी कर चुके हैं**
- **हमारा देश विश्व के सबसे युवा देशों में एक, आगामी 25 वर्ष तय करेंगे देश का भविष्य**
- **भारत ने गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होने का ले लिया है संकल्प**

युवाओं के सशक्तीकरण पर दिया जा रहा जोर

युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखने वाली नई नीतियों के युवा सशक्तीकरण पर केंद्रित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर प्रदान करने और नेतृत्व कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो, खेलों को प्रोत्साहित करना हो, वित्तीय प्रौद्योगिकी और

विनिर्माण क्षेत्रों का विस्तार करना हो, या कौशल विकास और इंटर्नशिप के अवसर पैदा करना हो, प्रत्येक पहल के केंद्र में युवा ही रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

आज के युवाओं के पास अपनी क्षमता प्रदर्शित करने को अभूतपूर्व अवसर

श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए यह अभूतपूर्व परिस्थिति है, क्योंकि हमारा देश विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले 25 वर्ष देश की दिशा तय करेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश की क्षमताएं, आकांक्षाएं और विश्व की अपेक्षाएं एक समान रूप से प्रदर्शित हो रही हैं। आज के युवा पहले से कहीं अधिक अवसरों के दौर में बड़े हो रहे हैं और सरकार उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को निखारने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से विकसित भारत की मजबूत नींव रखे जाने की बात कहते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर केंद्रित है। इसमें व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया गया है। बच्चों को रटने के बजाय सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रश्न पूछने का साहस पैदा किया गया है और समस्या-समाधान कौशल विकसित किए गए हैं। पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बहुविषयक अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षा, खेलों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहा है। देशभर में लाखों बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान में लगे हुए हैं। स्कूली स्तर पर भी छात्रों को रोबोटिक्स, एआई, सतत विकास और डिजाइन विचार प्रक्रिया से परिचित कराया जा रहा है। इन प्रयासों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में अध्ययन करने का विकल्प भी प्रदान किया है। इससे सीखना आसान हो गया है और बच्चों को विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों ने यह नहीं देखा कि रास्ता कितना कठिन था, बल्कि यह देखा कि रास्ता सही है या नहीं, और आज भी उसी भावना की आवश्यकता है। देश के युवाओं से बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और कभी भी अपना आत्मविश्वास न टूटने देने की उम्मीद जताते हुए श्री मोदी ने उल्लेख किया कि देश का भविष्य बच्चों और युवाओं के भविष्य में चमकेगा। बच्चों और युवाओं का साहस, प्रतिभा और समर्पण राष्ट्र की प्रगति का मार्गदर्शन करेगा। इसी विश्वास, जिम्मेदारी और निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि हमारे गौरवशाली अतीत वाले राष्ट्र की युवा पीढ़ी के पास प्रेरणादायक विरासत है। हमारा देश कुछ भी हासिल करने में सक्षम है।■

भारत दस वर्षों में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से हो जाएगा मुक्त

देश की आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता हावी रहने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मानसिकता का बीज 1835 में ब्रिटिश राजनेता मैकाले ने बोया था और आजादी के बाद भी इसे मिटाया नहीं जा सका। लेकिन भारत अब गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने का संकल्प ले लिया है और घोषणा की है कि भारतीय बलिदानों और वीरता की स्मृतियों को अब दबाया नहीं जाएगा और देश के नायकों और नायिकाओं को अब हाशिए पर नहीं रखा जाएगा। इसीलिए वीर बाल दिवस पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2035 में मैकाले की साजिश के 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे और शेष 10 वर्षों में भारत गुलामी की मानसिकता से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेगा। एक बार जब देश इस मानसिकता से मुक्त हो जाएगा, तो वह स्वदेशी परंपराओं पर अधिक गर्व करेगा और आत्मनिर्भरता के पथ पर और आगे बढ़ेगा। मैकाले ने भारत की भाषाई विविधता को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अब जब देश गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहा है, तो भाषाई विविधता एक शक्ति बन रही है।

व्यापार, पर्यटन व रणनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन रहा अंडमान और निकोबार

सहकार जागरण टीम

- **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री विजय पुरम में अस्पतालों व सड़कों सहित 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, 58 करोड़ की योजना लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी**
- **अंडमान और निकोबार को वैश्विक महत्व के केंद्र के रूप में मजबूत करने की भारत सरकार की व्यापक विकास योजना के तहत 373 करोड़ रुपए का उपहार**

अंडमान और निकोबार भारत की रणनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस द्वीप समूह को सामरिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया है। यह पहल अंडमान और निकोबार को वैश्विक महत्व के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए एक व्यापक विकास योजना का हिस्सा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को द्वीप समूह के श्री विजय पुरम में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह हमारी संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। सरकार अंडमान-निकोबार को अंतरराष्ट्रीय स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन और एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का गंतव्य बना रही है। ग्रेट निकोबार परियोजना से यह द्वीप वैश्विक कार्गो हब, पर्यटन केंद्र और भारत की सामरिक सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के एक दशक बाद यह स्थान दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए जाने वाला स्थान बन जाएगा। श्री शाह ने कहा कि विरासत को खोए बिना पर्यावरण को सुरक्षित और सुरक्षा को सुदृढ़ रखते हुए इस द्वीप समूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के प्रति सरकार संकल्पित है और इसे विकसित

आजाद भारत के हर नागरिक के लिए तीर्थभूमि

श्री शाह ने कहा कि यह भूमि आजाद भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थभूमि है क्योंकि यहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति, एकांत को संकल्प और यातना को स्वाधीनता तक सहन कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसी भूमि पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सेलुलर जेल में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का लंबा समय काटा, जिनमें से कई देशभक्तों ने तो यहां दम तोड़ दिया और कई वीरों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उन बलिदानियों को याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन शूरवीरों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सबसे पहले आजाद भारत की इसी भूमि पर तिरंगा फहराया था। नेताजी की स्मृति और उनके उद्गारों के सम्मान में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पोर्ट ब्लेयर का नामकरण श्री विजयपुरम किया और दो अंडमान-निकोबार के द्वीपों का नाम 'शहीद' और 'स्वराज' रखा है। उन्होंने इस द्वीप समूह पर हर द्वीप को स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों का नाम देकर देशभर में गुलामी की निशानियों से मुक्ति पाने का अभियान शुरू किया है। श्री शाह ने कहा कि सेल्युलर जेल में प्रज्वलित मशाल व वीर सावरकर जी का स्मारक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्ष गाथा दुनियाभर में पहुंचा रहा है और यह बता रहा है कि यहां कई महान आत्माओं ने अपना बलिदान दिया। आजादी के आंदोलन की एक अमूर्त प्रतिकृति के रूप में हर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति भी यहां देखी जा सकती है।

भारत में योगदानकर्ता बना रही है। यहां ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहां मत्स्य संपदा और कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों में विकास की शुरुआत हुई है। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम अपील के तहत यहां 24 लाख पौधरोपण कर हमने पर्यावरण की भी चिंता की है।

व्यापक विकास योजना के तहत श्री शाह ने विजय पुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से हमारे द्वीप समूहों के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। 315 करोड़ रुपए की नौ बड़ी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और दो परियोजनाओं के शुभारंभ से एक ही दिन में 373 करोड़ रूपए की लागत से विकास का उपहार इस द्वीप समूह को मिला है। इनमें अस्पतालों व सड़कों सहित एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र भी शामिल है। श्री शाह ने 58 करोड़ की योजना लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जहां अंडमान-निकोबार को देश के खजाने पर बोझ मानती थी, वह अब यह देश के खजाने में योगदान देने में सक्षम बन रहा है। पिछले 11 वर्षों में आया यह बदलाव देश के कण-कण को भारत माता मानकर उसे समर्पित रहने के संकल्प का परिणाम है।

भारत 2047 में हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम हो

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास का नया अध्याय गढ़ने का काम किया है। देश में आर्थिक विकास हो रहा है और हम दुनिया के उत्पादन का हब बन रहे हैं।साथ ही, देश सुरक्षित हो रहा है और परंपराओं को पुनर्जीवित कर अपनी संस्कृति व इतिहास के आधार पर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का 11वें से चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है और दो ही साल में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने संकल्प लिया है और देश की 140 करोड़ जनता को भी यह संकल्प दिलाया है कि आजादी की शताब्दी के समय भारत हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होगा।इस लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात् विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और हर भारतीय को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प भी लेना होगा।

तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण

श्री शाह ने श्री विजयपुरम में तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया और कहा कि भारत नए कानूनों द्वारा प्रदान किए गए ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर और फॉरेंसिक-आधारित सबूतों के साथ तेज और त्रुटिहीन न्याय देने में आगे बढ़ रहा है। अंडमान और निकोबार के सभी वकीलों, युवा विद्यार्थियों, विशेषकर महिलाओं और न्याय कार्यों से जुड़े कर्मियों सहित सभी को नए कानूनों पर यह प्रदर्शनी देखने की प्रेरणा देते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन और तकनीक को मिलने वाले कानूनी आधार के बारे में जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि नए कानून समय पर न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित हैं।■

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन

भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था : प्रधानमंत्री श्री मोदी

सहकार जागरण टीम

हाल के वर्षों में भारत ने जो तीव्र प्रगति की है, उसमें गुजरात और यहां की जनता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत से वैश्विक उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कही।

देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में है और कृषि उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, भारत की ग्रोथ फैक्ट शीट दरअसल 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र की सफलता की कहानी है। पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया में मोबाइल डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है, और यूपीआई वैश्विक स्तर पर नंबर वन रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। अब भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है, सोलर पावर जनरेशन में शीर्ष तीन देशों में शामिल है, तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, और

- **भारत की ग्रोथ फैक्ट शीट दरअसल 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र की सफलता की कहानी है**
- **भारी वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत अभूतपूर्व निश्चितता के युग से गुजर रहा है**

दुनिया के शीर्ष तीन मेट्रो नेटवर्क में से एक है।

दुनिया के विशेषज्ञों और संस्थानों द्वारा भारत को लेकर जताए जा रहे सकारात्मक रुख का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कह कि आईएमएफ भारत को वैश्विक विकास का इंजन मान रहा है, एसएंडपी ने 18 वर्षों के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड की है और फिच रेटिंग्स ने भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता व राजकोषीय विश्वसनीयता की सराहना की है। भारत पर यह वैश्विक भरोसा इसलिए है, क्योंकि भारी वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत अभूतपूर्व निश्चितता के युग से गुजर रहा है। भारत में राजनीतिक स्थिरता है, नीतियों में निरंतरता है और एक उभरता हुआ नया मिडिल क्लास है जिसकी क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि आज भारत असीमित संभावनाओं का देश बन गया है।

सौराष्ट्र और कच्छ की जुझारू शक्ति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुजरात के ये क्षेत्र हमें सिखाते हैं कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि

ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रयास किया जाए तो सफलता निश्चित है। अतीत के संघर्षों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में एक विनाशकारी भूकंप का सामना किया था। यह वही सौराष्ट्र है जो वर्षों तक भीषण सूखे की मार झेलता रहा, जहां माताओं और बहनों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बिजली अनिश्चित थी और हर तरफ कठिनाइयां ही कठिनाइयां थीं। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों ने अपने कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ से अपनी नियति को बदल कर रख दिया है।

सौराष्ट्र और कच्छ की औद्योगिक ताकत की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज ये क्षेत्र केवल अवसरों के क्षेत्र नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा के मुख्य आधार बन चुके हैं। ये क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाले प्रमुख केंद्र बन रहे हैं और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजकोट की औद्योगिक विविधता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि अकेले राजकोट में 2.5 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। यहां स्क्रूड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स और लग्जरी कारों के लाइनर्स तक बनाए जाते हैं। अब यहां हवाई जहाज, लड़ाकू विमान और रॉकेट के पुर्जे भी निर्मित हो रहे हैं। यह क्षेत्र कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई-प्रिसिजन और हाई-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। साथ ही यहां का आभूषण उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है।

गुजरात की औद्योगिक शक्ति का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने अलंग का उदाहरण दिया। अलंग में दुनिया का सबसे बड़ा शिप-ब्रेकिंग यार्ड है, जहां दुनिया के एक-तिहाई जहाजों की रीसाइक्लिंग की जाती है। टाइल्स उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े टाइल्स उत्पादकों में से एक है, जिसमें मोरबी जिले का सबसे बड़ा योगदान है। यहां मैन्युफैक्चरिंग न केवल लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी है, बल्कि इसके मानक भी वैश्विक स्तर के हैं।

धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा धोलेरा में स्थापित की जा रही है। इस क्षेत्र में निवेश के लिए जमीन पूरी तरह तैयार है। यहां न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बल्कि हमारी नीतियां भी स्थिर और अनुमानित हैं और हमारा विजन दीर्घकालिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र अब भारत की ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन मोबिलिटी और ऊर्जा सुरक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। कच्छ में 30 गीगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड ऊर्जा पार्क होगा। यह पार्क पेरिस शहर से पांच गुना बड़ा होगा। इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा केवल एक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि एक कमर्शियल लेवल की वास्तविकता बन चुकी है। कच्छ और जामनगर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के बड़े केंद्र बन रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ में एक विशाल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है।

सौराष्ट्र और कच्छ की एक और बड़ी ताकत के रूप में यहां के वर्ल्ड-क्लास पोर्ट्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचता है। पीपावाव और मुंद्रा पोर्ट अब ऑटोमोबाइल निर्यात के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। पिछले वर्ष गुजरात के बंदरगाहों से लगभग 1.75 लाख वाहनों का निर्यात किया गया। गुजरात सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है और सीफूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया गया है।

अंडमान-निकोबार में संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बोले श्री अमित शाह

तीन नए कानूनों से देश में सुनिश्चित होगा समयबद्ध न्याय

2029 तक देश के हर राज्य में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी या सेंट्रल फॉरेंसिक लैब होगा

- नए आपराधिक कानूनों से जांच में तेजी आ रही है और दोष सिद्धि दर भी बढ़ रही है
- अगले पांच वर्षों में देश भर में होंगे फॉरेंसिक लैब, 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश
- गरीबों व महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं ई-एफआईआर व जीरो एफआईआर
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों को भी नए आपराधिक कानूनों में प्राथमिकता

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद समय पर न्याय मिले। हम 2029 तक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जिसमें तीन साल की अवधि में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजय पुरम में संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान इन उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि हमने वैज्ञानिक सुधार, सुरक्षित डेटाबेस का विकास, तकनीक और मानव संसाधन क्षमता निर्माण, संस्थाओं का सशक्तीकरण और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में कदम उठाए हैं। नए आपराधिक कानूनों में टेक्नोलॉजी को महत्व दिया गया है। ई-समन और ई-साक्ष्य जैसे सुधार किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों को भी नए आपराधिक कानूनों में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर गरीबों और महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है।

श्री शाह ने कहा कि देश में कोई ऐसा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश नहीं रहेगा जहां फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी या सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में से कोई एक संस्था नहीं हो। राज्यों की एफएसएल, फॉरेंसिक वैन और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

नए कानूनों से तेज गति से अपराधियों को मिल रही सजा

तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद जल्द परिणाम लाने के प्रयासों के अच्छे प्राथमिक नतीजे मिल रहे हैं। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल में एक बच्ची से बलात्कार के दोषी को 62 दिनों में फांसी की सजा सुनाने और बिहार के सीवान जिले में ट्रिपल मर्डर की घटना में सिर्फ 50 दिनों में दो दोषियों को सजा सुनाने का जिक्र किया और कहा कि इन मामलों से साबित होता है कि हमें सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। अब हम 2029 तक सभी राज्यों में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करके हर साल 35,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ तैयार करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें देश भर में फॉरेंसिक लैब का जाल बुनने के लिए अगले पांच वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं।■

ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े देश के सभी पुलिस स्टेशन

श्री शाह ने कहा कि नवंबर 2025 तक देश के हर पुलिस स्टेशन को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) पर ऑनलाइन कर दिया है, जिससे हर एफआईआर सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध है। जहां सात लाख प्राथमिकी का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है, वहीं 22 हजार कोर्टस को ई-कोर्टस से जोड़ा गया है। ई-प्रिजंस में देश भर की जेलों के दो करोड़ 20 लाख कैदियों का डाटा सेंट्रल सर्वर में उपलब्ध है। ई-प्रोसिक्यूशन में लगभग दो करोड़ प्रोसिक्यूशन का डाटा उपलब्ध है। नौ लाख 44 हजार नार्को अपराधियों का डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। मानव तस्करी में लिप्त तीन लाख 65 हजार अपराधियों का डाटा ऑनलाइन हो चुका है। भारत ने तेज और सटीक नतीजे देकर और रिकॉर्ड उच्च दोषसिद्धि दर हासिल करके तेज और बिना किसी गलती के न्याय देकर फॉरेंसिक जांच में वैश्विक मानक हासिल किए हैं।

अहमदाबाद में 'युवा बिजनेस महासम्मेलन- 2025' में बोले श्री अमित शाह

स्वरोजगार से होगा आत्मनिर्भर व समृद्ध भारत का निर्माण

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार स्वरोजगार से आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में युवाओं के विकास के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना और 'वोकल फॉर लोकल व लोकल फॉर ग्लोबल' तक की चैन तैयार की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को अहमदाबाद में 'युवा बिजनेस महासम्मेलन- 2025' के दौरान व्यक्त किया। विश्व उमिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में करीब 15 हजार युवाओं के बीच श्री शाह ने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में लंबी छलांग लगाई है। सरकार ने देश के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में जहां पूरे देश में 500 स्टार्टअप थे, वहीं आज यह संख्या दो लाख छह हजार हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय तक देश में केवल चार यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, जो अब 120 हैं। इन स्टार्टअप्स के माध्यम से 18 लाख स्थायी रोजगार का सृजन हुआ है और लाखों लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिला है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में जब श्री मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला, उस समय हम विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन, पिछले 11 वर्षों में ही भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि 2047 में जब देश की आजादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाए, तब भारत पूरे विश्व में नंबर एक पर हो। ऐसे भारत की रचना करने के लिए दो कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं-पहला आत्मनिर्भर भारत और दूसरा स्वदेशी का आग्रह। उन्होंने कहा कि अगर हमने इन्हें पूरा कर लिया तो हमें दुनिया में हर क्षेत्र में नंबर एक पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दुनियाभर में भारत के उत्पादों का निर्यात हो और भारत देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत फायदा होगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई

श्री शाह ने विश्व उमिया फाउंडेशन बिजनेस नेटवर्क एप्लिकेशन का शुभारंभ किया, जो युवा उद्यमियों को जोड़ने के साथ-साथ निवेशकों और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि आज के युग में सूचना बहुत बड़ी ताकत है। सरकार ने इस ऐप के माध्यम से बेहद प्रोफेशनल तरीके से पाटीदार समाज के युवाओं के लिए बिजनेस के संरक्षण, संवर्धन और वृद्धि के लिए सारी जरूरतें पूरी करने का प्रयास किया है। श्री शाह ने कहा कि गुजरात व देश के अर्थतंत्र को गति देने के उद्देश्य से मां उमिया का मंदिर सनातन धर्म का ऐसा केंद्र बनने वाला है, जिसने संस्कृति को भी जमीन पर उतारा है, जहां एक ही स्थान पर समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिल रहा है। इस फाउंडेशन ने सैंकड़ों युवाओं को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ाने, विकास और प्रकृति के संतुलन के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया है। ■

'मन की बात' का 129वां एपिसोड

गर्व, एकता और आत्मविश्वास का साल रहा 2025

सहकार जागरण टीम

अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 129वें एपिसोड में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ देश के आगे बढ़ने की बात कहते हुए वर्ष 2025 की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने इसे गर्व, एकता और आत्मविश्वास का साल बताया और कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। हमने दुनिया को बता दिया कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। यह अभियान भारत की सुरक्षा नीति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बना। इस ऑपरेशन के दौरान देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीयों ने भारत के प्रति अपना समर्थन दिखाया। दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आईं। लोगों ने खुलकर इसका समर्थन किया।

वर्ष 2025 में विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। देश ने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का सफल परीक्षण किया। इस प्रकार ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। इस दौरान भारत ने पर्यावरण सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई पहल भी शुरू की। अब देश में चीतों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है।

महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अनोखी विरासत सब एक साथ देखने को मिलीं। साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आस्था और भक्ति के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचे। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर में झंडा फहराने की सेरेमनी ने हर भारतीय को गौरवान्वित कर दिया।

प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् गीत के 150 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने देशवासियों को एकजुट किया, उसी तरह वंदे मातरम् ने भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और गर्व का भाव जगाया। काशी-तमिल संगम का भी जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश की सांस्कृतिक एकता और मजबूत हुई है। तमिल भाषा को सीखने और समझने की पहल ने युवाओं को प्रेरित और उत्साहित किया। यह भारत की विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण रहा।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मणिपुर के मोइरांगथेम सेठ का भी जिक्र किया। सेठ ने सोलर पावर के जरिए बिजली की समस्या का हल निकाला। श्री मोदी ने कहा कि यह 'जहां चाह, वहां राह' का जीता-जागता उदाहरण है।

श्री मोदी ने कहा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने नया इतिहास रचा है। पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की जीत, पैरा एथलीट्स की उपलब्धियां और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत की सामूहिक ताकत, आत्मविश्वास और एकजुटता की पहचान बन गया। आगामी वर्ष देश के लिए और भी संभावनाएं लेकर आएगा।■

एनडीडीबी के कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा

सामाजिक परिवर्तन की सशक्त वाहक हैं सहकारी संस्थाएं

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दूरदर्शी विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन जनकल्याण और सामाजिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न पहलों और सहकारिता के विस्तार से सहकारी संस्थाएं अब केवल आर्थिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सशक्त वाहक हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) फाउंडेशन के 'पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में इन विचारों को व्यक्त किया। पोषण सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट एवं सहकारी सहभागिता पर जोर देते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि सीएसआर सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बनकर उभरा है और यह परोपकार से आगे बढ़कर रणनीतिक सामाजिक निवेश का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि शिशु संजीवनी जैसे कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि सहकारी ढांचा स्थानीय भागीदारी, पारदर्शिता और प्रभाव सुनिश्चित करके सीएसआर संसाधनों को ठोस सामाजिक परिणामों में प्रभावी ढंग से परिवर्तित कर सकता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की गिफ्ट मिल्क और शिशु संजीवनी जैसी पहलों की सराहना करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि ये पहल आकांक्षी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हैं और अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएसआर के माध्यम से 'एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन' जैसे संस्थागत मंचों का समर्थन करना केवल एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण में एक सक्रिय योगदान है।

'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण में सहकारी संस्थाएं सक्रिय योगदान दे रहीं हैं

कुपोषण की जटिल चुनौती से पार पाने के लिए समन्वित कार्रवाई पर भारत सरकार गंभीरता से पहल कर रही है। इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय का एक सशक्त उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री के 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के विजन के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पशुपालन और मत्स्य विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकसाथ मिलकर काम कर रहे हैं। वास्तव में, विकसित भारत के निर्माण और देश के सामाजिक तथा आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुपोषण का उन्मूलन परम आवश्यक है।

कार्यक्रम में एनडीडीबी ने एक छत्र संगठन की भूमिका निभाते हुए सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को आगे बढ़ाया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के पोषण के नतीजों को बेहतर बनाना है। बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक, नवोन्मेषी एवं सतत रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों, डेयरी सहकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों एवं विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्र रूपी लाभार्थी संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्रदान किया।

इस राष्ट्रीय आयोजन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह, राज्य मंत्री (मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज) प्रो. एस. पी. सिंह बघेल सहित सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी एवं मंत्रालय के अन्य गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ■

लाठीकाटा समिति ने जन औषधि केंद्र खोलकर आदर्श स्थापित किया

सहकार जागरण टीम

सहकारी समितियां अब अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रही हैं। खेती-किसानी के क्षेत्र से आगे बढ़कर अब दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं और लोगों को सशक्त बना रही हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित सहकारी समिति लाठीकाटा लैंप्स लिमिटेड परंपरगत रूप से किसानों को कृषि इनपुट व कृषि ऋण के साथ ही अब सस्ती व उच्च गुणवत्तायुक्त दवाएं और महिला स्वच्छता उत्पाद भी उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग से समृद्धि) के विजन और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में लाठीकाटा लैंप्स ने सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत एक जन औषधि केंद्र शुरू किया। इसके पहले बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय समिति (लैंप्स) किसानों को कृषि इनपुट के रूप में उर्वरक, बीज, कृषि में इस्तेमाल होने वाली अन्य जरूरी चीजें व कृषि ऋण उपलब्ध कराती रही है और अब जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को बहुत कम दाम पर गुणवत्तायुक्त दवाएं और अन्य चीजें उपलब्ध करा रही है। दवाओं को बाजार के मुकाबले 80 से 90 प्रतिशत कम दाम पर लोगों को प्रदान किया जा रहा है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। सेहतमंद होने से वे उत्पादक कार्य कर पा रहे हैं और विकास में भागीदार बन रहे हैं।

ग्रामीणों और अर्ध-शहरी, विशेषकर आदिवासी (ट्राइबल) इलाकों में रहने वाले समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के

उद्देश्य से कार्य कर रही समिति सस्ती दवाओं के साथ मेडिकल व सर्जिकल उपकरण और महिलाओं के लिए स्वच्छता के साधन भी उपलब्ध कराती है। इसके परिणामस्वरूप गांवों व पिछड़े इलाकों की महिलाओं को सहूलियत होती है। वे केंद्र से कम दाम पर जरूरी चीजें खरीद पाती हैं। इससे उनको बीमारियों से छुटकारा मिलता है और वे सेहतमंद होती हैं। इससे उनकी आर्थिक बचत होती है और वे उत्पादक कार्यों में भी सहभागी बनती है। इसके परिणामस्वरूप जहां उनका आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है, वहीं उनमें आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। इससे उनका विस्तार हो रहा है। वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रही हैं।

जन औषधि केंद्र से जहां लोगों को सस्ते दामों पर दवाएं मिल रही हैं, वहीं इससे स्थानीय अवसर पर रोजगार का अवसर भी बन रहा है। केंद्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। सुंदरगढ़ में भी खुले जन औषधि केंद्र में कुछ युवाओं को रोजगार मिला है। इससे युवकों व उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहा है। दवाओं व अन्य चीजों की बिक्री से जन औषधि केंद्र की कमाई भी हो रही है। केंद्र को हर माह 25 से 30 हजार रुपए की आय हो जाती है। इससे केंद्र धीरे-धीरे दवाओं का स्टाक बढ़ाता जा रहा है। केंद्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। अब इन दवाओं के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ता, बल्कि कम दाम पर केंद्र में ही दवाएं मिल जाती हैं। सहकारी समिति की इस व्यवस्था से लोग खुश हैं। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है कि सहकारिता से समृद्धि का मंत्र जमीनी स्तर पर प्रभावी हो रहा है। समिति की इस पहल से दूसरी समितियां भी प्रेरित हो रही हैं और वे भी अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही हैं। ■

डॉ.ए.के. रॉय

सामूहिकता का विश्वास जगाती है सहकारिता

सहकारिता भविष्य के ठोस आधार की अग्रदूत है। कोऑपरेटिव समाज की तीन स्तरीय व्यवस्थाओं सामाजिक संगठन, पर्यावरणीय और आर्थिक आधार के साथ जोड़ती है। सहकारिता में सामाजिक, आर्थिक सहभागिता तथा शिक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही सहकारिता सामूहिकता के आधार पर लोगों में इस बात का विश्वास जगाती है कि वे स्वयं के विकास की जिम्मेदारी खुद लें। सहकारिता के माध्यम हमेशा से ही यह प्रयास किया जाता है कि लोग अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर चीजों के हकदार हों और अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सुधार के ताजा प्रयासों से सहकारिता के विकास को बल मिला है। इससे जहां पुराने व्यवस्था को बदलने में सहूलियत हुई है वहीं सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर निष्क्रिय सहकारी समितियां सक्रिय होने लगी हैं वहीं कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिला है। प्राथमिक सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए कई ऐसी पहल की गई है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होने लगा है।

सहकारिता एकमात्र सामाजिक संगठन है, जिसके सिद्धांत और मूल्य वैश्विक स्तर पर पूरी तरह मान्य हैं। सहकारिता का गठन सहकारी समितियों के सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है। सदस्य एक समूह में रहते हुए एक दूसरे सदस्य को लाभ के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसका उपयोग मुद्दों के समाधान के लिए भागीदारी और सहभागिता प्रमुख घटक होते हैं। देश के करोड़ों लोगों की सामाजिक, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने युवाओं को सहकारिता के प्रति जागरुक करने और इसमें उहें करियर बनाने की पहल की है। इसके तहत देश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

सतत विकास एक संगठनात्मक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर से बेहतर प्रयोग बनाना है। सतत विकास का मतलब मानव संसाधनों का इस तरह के विकास को माना जाता है जिसमें पर्यावरणीय संसाधनों से अनुकूलता बनाते हुए विकास लक्ष्यों को हासिल किया जाए।

वर्ष 1987 में जारी ह्यद बंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे। वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में इसका प्रमुख योगदान है। भविष्य की जरूरतों के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के रूप में देखा जाता है। सतत प्रबंधन भी इसी कड़ी में शामिल किया जाता है, इसमें संगठनात्मक प्रथाएं शामिल हैं जो अंततः सतत विकास की ओर ले जाती हैं। आर्थिक उत्पादन और उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जाता है, जो पर्यावरणीय संरक्षण के प्रभावों को देखते हुए संसाधनों को संरक्षित करने पर जोर देता है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढी की भी जरूरतें होंगी और संसाधनों को उनके लिए भी बचाकर रखना होगा।

सतत विकास लक्ष्य इसी उद्देश्य के साथ एक टीम भावना के साथ काम करने का संकल्प है, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है और उद्यम स्तर पर स्वस्थ विकास को समर्थन मिलता है। इस संदर्भ में क्षमता निर्माण एक अहम पहलू है जिसमें रणनीतिक कार्ययोजना और प्रबंधन संसाधन को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता सतत विकास मूल्यों को सही तरीके से अनुपालन करती है, इसमें समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए समग्र सामाजिक विकास की अवधारणा पर काम किया जाता है। सहकारी समितियों की किफायती और टिकाऊ तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए समितियों की क्षमताओं को बढ़ाया जाता है।

सहकारिता को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का बेहतर माध्यम कहा जा सकता है, जिसको तीन मुख्य बिंदुओं से आसानी से समझ सकते हैं, गरीबी मिटाने में सहकारिता अहम भूमिका निभा सकती है। सहकारिता के जरिए व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन संभव है, सहकारिता के जरिए लैंगिक समानता संभव है जो सतत विकास के लिए जरूरी है। नये मॉडल बायलॉज में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सफल सहकारी समितियों के संचालन के लिए यह जरूरी है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए विकास रणनीति तैयार करना, बेहतर सहकारिता के लिए अधिक महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है। व्यवसायों से परे लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। सहकारिता सतत प्रक्रिया की अग्रदूत है, सतत विकास रणनीति के लिए सहकारी समितियों की समूह कार्य योजना सामूहिक प्रयासों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सतत विकास सहकारी समितियों की ताकत है। सतत विकास को सहकारिता का ह्रदय कहा जा सकता है।■

पूर्व प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (आईजीआईसीएम) लखनऊ

एनसीयूआई के युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एनसीसीई ने सफल सहकारी व्यापार मॉडल के तौर पर सहकारी समिति के पंजीकरण, दस्तावेज और उपनियमों का मसौदा तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 53 युवाओं को व्यावहारिक ट्रेनिंग प्रदान की, जिसमें एनसीयूआई की उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह और कार्यकारी निदेशक श्री राजीव शर्मा व श्री वेद प्रकाश सेतिया ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

नेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन (एनसीसीई) ने युवाओं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने पर पांच दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 11 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। एनसीयूआई की डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती सावित्री सिंह ने आयोजन का शुभारंभ किया और सामाजिक-आर्थक विकास में कोऑपरेटिव्स के महत्व को समझाया।

डिप्लोमा प्रोग्राम के प्रतिभागियों ने कृभको का दौरा कर राष्ट्रीय स्तर के कोऑपरेटिव फेडरेशन के कामकाज, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की, जहां सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में उन्हें वैज्ञानिक टेस्टिंग प्रक्रियाओं, क्वालिटी कंट्रोल उपायों और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उनके महत्व के बारे में बताया गया।

कोहिमा में राज्य की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए नागालैंड कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्यों और फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया। सहकारी समितियां - आर्थिक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक विषय पर विमर्श में नाबार्ड, एनसीडीसी, एनडीडीबी, एनसीयूआई, एनसीईएल, एनसीओएल, बीबीएसएसएल, एपेडा और इफको सहित शीर्ष सहकारी संघों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट आनंद (इरमा)- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेघालय के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के अधिकारियों ने फील्ड विज़िट के जरिए क्लासरूम से बाहर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का अनुभव प्राप्त किया।

अरुणाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव को मजबूत बनाने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, आणंद के सहयोग से पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कोऑपरेटिव के सिद्धांतों से लेकर बिजनेस प्लान बनाने, फाइनेंशियल ऑपरेशन और इंटर-डिपार्टमेंटल तालमेल जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

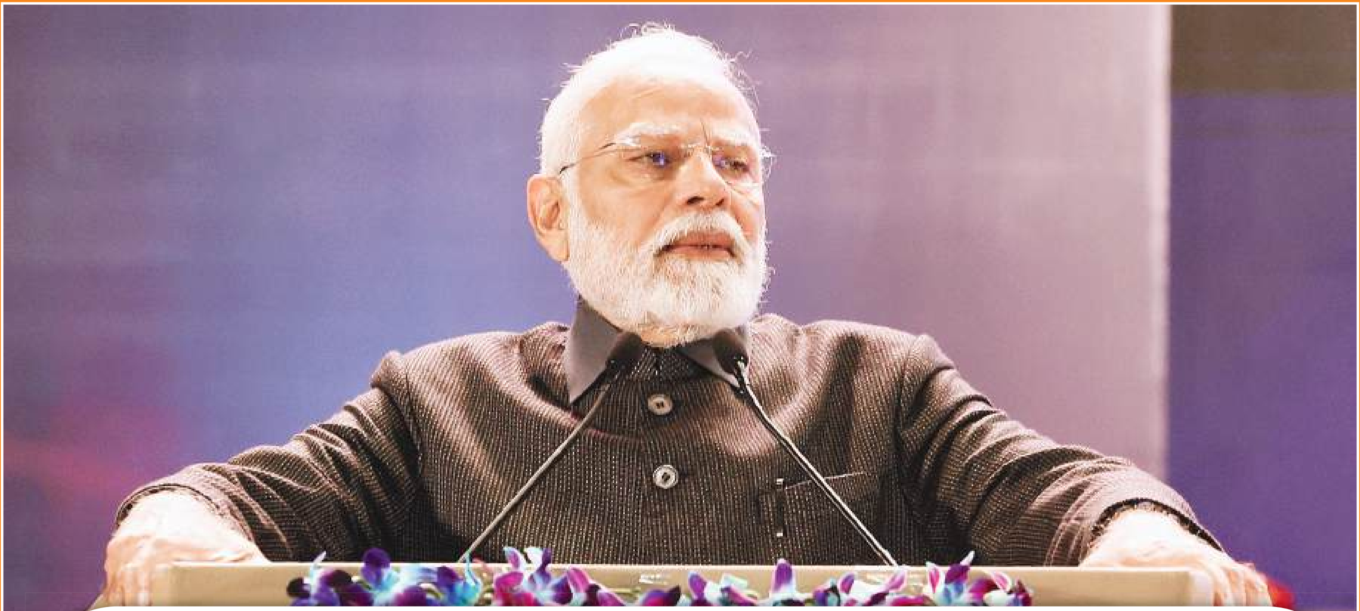

आज युवाओं के सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही हैं। युवाओं को राष्ट्र-निर्माण के केंद्र में रखा गया है। 'मेरा युवा भारत', ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही हैं। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (CEAS-LMS) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए राजीव शर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक : राजीव शर्मा

RNI No: DLHIN/25/A0141
Published on 01.03.2026 Postal Registration No: DL-SW-01/4214/2023-24

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ